आवास योजना शीघ्र पूरा कराना

4. श्री विनोद नारायण झा--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''गरीबों के आवास का सपना अधर में'', के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बी०एस०यू०पी० योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए पटना एवं बोध गया में कुल 709.99 करोड़ रुपये की लागत से 22372 आवास बनाया जाना है, जिसके निर्माण की जिम्मेवारी हुडको को दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि जमीन के अभाव में तथा हुडको की लापरवाही के कारण उक्त दोनों जिलों के गरीबों के लिए बनने वाले घरों की योजना साकार नहीं हो पा रही है, जबकि इसके लिए केन्द्र सरकार ने 318.12 एवं राज्य सरकार ने 391.86 करोड़ रु० निर्माण के लिए स्वीकृत कर चुकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शहरी गरीबों के आवास योजना को शीघ्र पूरा कराने हेतु सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वितरकों की संख्या बढ़ाना

5. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 जनवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''केन्द्र बढ़ाए गैस वितरकों की संख्या'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में गैस वितरकों के पास क्षमता से अधिक गैस उपभोक्ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार का एलपीजी वितरकों की संख्या आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में एलपीजी की कमी की समस्याओं से उबरने के लिए वितरकों की संख्या बढ़ाने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चावल की कमी दूर करना

6. श्री अख्तरूल ईमान--दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''सूबे में चावल की होगी भारी कमी'' के संदर्भ में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष धान उत्पादन का लक्ष्य 70.45 लाख टन निर्धारित है, किन्तु वर्षा की कमी तथा सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण राज्य में केवल 28.30 लाख टन धान उत्पादन की उम्मीद है;

(2) क्या यह बात सही है कि धान आच्छादन का लक्ष्य 30.50 लाख हेक्टेयर था, जिसके विरुद्ध केवल 24.00 लाख हेक्टेयर ही आच्छादन हुआ है जिस कारण भी चावल की भारी कमी होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में चावल की कमी को दूर करने के लिए कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है ?

जमीन उपलब्ध कराना

7. श्री तार किशोर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2011को प्रकाशित शीर्षक ''जमीन देने में सुस्ती'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में एक लाख 93 हजार महादलित परिवारों के पास जमीन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक मात्र 17,379 महादलित परिवारों के बीच मात्र 521.31 एकड़ जमीन बन्दोबस्त की गयी है, जो लक्ष्य का 33.65 प्रतिशत है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे भूमिहीन महादलित परिवारों को वास हेतु जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

8. श्री अख्तरूल ईमान--दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 को हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''खाद की कालाबाजारी करोड़ों में'' के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में खाद की कालाबाजारी होने के कारण किसानों को प्रति बैग 100-150 रुपया अधिक मूल्य पर खाद की खरीदारी करनी पड़ती है, जिससे प्रतिवर्ष किसानों को 150 करोड़ रुपया का नुकसान होता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कालाबाजारी करने वाले खाद विक्रेताओं तथा उसको संरक्षण देने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य प्राप्त करना

9. श्री तार किशोर प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''लेकिन धान खरीद में हम पीछे'' के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे देश में अबतक 2.54 करोड़ टन धान की खरीद की गयी है, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी सिर्फ 2.83 लाख टन है;

(2) क्या यह बात सही है कि पंजाब, छत्तीसगढ़ हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की देश की कुल खरीद में हिस्सेदारी 2.31 करोड़ टन है;

(3) क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों में बिहार देश के दस अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य एजेंसियों द्वारा बिहार के किसानों से धान की खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन-सा आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है ?

पटना:
दिनांक 24 फरवरी, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 117-डी०टी०पी०--450